न होने दे कर उस का ठीक वितरण किया जाये ।

श्री ल० ना० मिश्र : जैसा कि माननीय सदस्य, श्री भागवत झा आज़ाद ने कहा है, आदरणीय प्रधान मंत्री, पंडित जवाहरलाल नेहरू के दिमाग़ में यह बात आई थी और उन्होंने इस समिति की स्थापना की थी । उस का कारण यह था कि सरकार के सामने यह बात आई थी और देश में यह हवा थी । यह सत्य भी है कि धनी और धनी हुए हैं । मैं यह नहीं मानता हूं कि ग़रीब और ग़रीब हो गए हैं, लेकिन इतना ज़रूर है कि धनी और धनी हो गए हैं । समिति की रिपोर्ट आई है । मैंने अपने आन्सवर में कहा है :

> "The conclusions arrived at in Part I of the Mahalanobis Committee Report have, naturally influenced the formulation of policies in this field."

इसलिए चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के आब-जेक्टिव्ज़ और उद्देश्यों में इस बात का ख़याल रखा गया है ।

Shri Warior: May I know whether it is not a fact that the party in power has already in a party way taken a decision on the monopolies commission and that is why the recommendations including the dissenting note are not implemented?

Shri L. N. Mishra: There is no question of anything not being implemented; it is being considered; it is in fact before the Cabinet and in a few days time the decision will be announced.

Shri Joachim Alva: Is the Government aware that the hundred wealthy families of India are today wealthier than at any time in the history of India, Puranic, Muslim, British, Congress and now, and also that these firms control two-thirds of the total advance of the banks of India? Is the Government aware of the existence of the monopolies commission in U.K., on the pattern of which we have built out organisation and that there in U.K. the monopolies commission is sitting regularly and firing even the biggest companies; in a recent case they fined the tyre company a big sum? Why not Government take some measures and do something quick?

Shri L. N. Mishra: The evil is there. The commission was appointed and the report has come. The hon. Member knows the recommendations; some of the recommendations are very radical and drastic and Government will consider it and will try to implement it as far as possible.

Shifting of Government Offices

***663. Shri N. R. Laskar:** Will the Minister of **Works, Housing and Urban Development** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 3379 on the 7th April, 1966 and state:

(a) the up-to-date progress made in shifting Government Offices in view of congestion in Delhi area;

(b) whether some Ministries/Attached Offices are reluctant to move away from the central location; and

(c) if so, the reasons therefor?

The Deputy Minister in the Ministry of Works, Housing and Urban Development (Shri Bhagwati): (a) Three offices out of the sixteen proposed to be shifted outside Delhi have so far moved out. They are:—

(i) The Central Water and Power Commission (Water Wing) to Faridabad.

(ii) The National Sample Survey Directorate (Bulk portion) to Faridabad.

(iii) The Fertilizer Corporation of India (part only) to Gorakhpur.

(b) Yes.

(c) The reasons are mainly administrative and functional inconveniences resulting from a shift outside Delhi.

Shri N. R. Laskar: I would like to know whether the Government has made any survey in some of the cities in our country where at least some of the offices from Delhi can be shifted and accommodated?

The Minister of Works, Housing and Urban Development (Shri Mehr Chand Khanna): The position in the beginning was a little helpful, but now we do not find accommodation in any one of the important cities on account of the growth of population as well as the increase in the number of offices required by the local Governments.

श्री यशपाल सिंह : क्या सरकार यह बतला सकती है कि गांधी जी ने देश के साथ विकेन्द्रीकरण का वादा किया था और आज सरकार इसलिए टाल रही है कि किसी भी इम्पार्टेंट सिटी में जगह नहीं है तो क्या लाखों देहात ऐसे नहीं हैं कि जहां इन दफ्तरों को शिफ्ट कियां जा सकता है ?

अध्यक्ष महोदय : आप के पास कम्नों में जगह नहीं है तो गांवों में इन दफ्तरों को भेज दीजिए ।

श्री यशपाल सिंह : बिल्कुल जगह हम देंगे ।

श्री मेहर चन्द खन्ना : दफ्तर तो वहां चलेगा जहां सुभीता होगा.....

श्री यशपाल सिंह : मुफ्त जमीन आप को देंगे ।

श्री मेहर चन्द खन्ना : ठीक है, मैं जानता हूं लेकिन गवर्नमेंट आफ इंडिया के आफिसर वहां से नहीं चल सकेंगे ।

Shri Shree Narayan Das: With regard to part (b) of the question, the hon. Minister has answered it in the affirmative. I would like to know what steps are being taken so that these offices and their attached offices may not be reluctant to move out.

Shri Bhagwati: We have tried to persuade them to shift to Faridabad and other places where we have given them accommodation but they refused.

Shri S. M. Banerjee: May I know whether it is a fact that there is a movement launched by the employees regarding the shifting of the offices from Delhi to other places, the reason being that they would have lost the benefit of Delhi being a Class I city, and whether any assurance will be given to them that if they shift to Faridabad or any other place which is not a Class I city, their total emolument will be protected there?

Shri Mehr Chand Khanna: That has been one of the causes which created a certain amount of diffidence on the part of the Government servants leaving Delhi and going to places like Faridabad.

Shri S. M. Banerjee: What is the Government's decision?

Shri Mehr Chand Khanna: We have taken up the matter with the Ministry of Finance and they feel that once we raise the status of Faridabad or some of the adjoining towns, it will create a very big problem for them. In that context, so far they have not agreed, but they have given some partial relief; but relief to the extent of the compensatory allowance as is being given in Delhi has not been agreed to by them yet.

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : श्रीमन्, मैं यह जानना चाहता हूं कि केन्द्रीय सरकार ने अपने कुछ नये कार्यालय बनाने के लिए गाजियाबाद के पास भी कुछ जमीन ली है, तो जो जमीन केन्द्रीय सरकार ने उत्तर प्रदेश सरकार के माध्यम से वहां ऐक्वायर की है क्या उस जमीन के दाम उत्तर प्रदेश सरकार को भेज

दिये हैं, यदि हां, तो कितना और उन किसानों को कब तक वह दाम मिल जायगा ?

श्री मेहर चन्द खन्ना : माननीय सदस्य ने मुझे भी चिटठी लिखी और प्रधान मंत्री को भी । पांच दस दिन हुए उनको मैंने तफसील में जवाब दिया है । जहां तक जमीन का ताल्लुक है, ऐक्वीजीशन होता है तो उसमें कम्पेन्सेशन तो स्टेट गवर्नमेंट असेस करती है . . .

श्री प्रकाश वीर शास्त्री : आप ने दे दिया या नहीं ?

श्री मेहर चन्द खन्ना: हमें जो कम्पेन्सेशन देना है, जिस वक्त भी रिक्वीजीशन आयेगा, तो मैं यह कहने के लिए तैयार हूं कि हमारे यहां कोई देरी नहीं होगी ।

Shri Kapur Singh: Is there any proposal to shift the Ministry of Works, Housing and Urban Development from Delhi, as far away from Delhi as possible and, if not, are the Government prepared to consider this proposal?

Shri Mehr Chand Khanna: I could not follow.

Mr. Speaker: Is there any proposal to shift the Ministry of Works, Housing and Urban Development from Delhi, and, if not, whether they are prepared to consider such a proposal.

Shri Mehr Chand Khanna: If it will give some satisfaction to the hon. questioner, if I get some share in Chandigarh, I might consider that proposal.

आदिवासियों का सामाजिक व आर्थिक स्तर

\+

*664. **श्री सिद्धेश्वर प्रसाद**
श्री रिशांग किशिंग :
श्री मे० क० कुमारन :

क्या योजना तथा समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने आदिवासियों के सामाजिक व आर्थिक स्तर को समाज के अन्य वर्गों के स्तर के बराबर लाने के लिये कोई विशेष कार्यवाही करने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो उसकी मख्य बातें क्या हैं; और

(ग) उन वर्गों का पिछड़ापन कब दूर हो जाने की सम्भावना है ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ल० ना० मिश्र): (क) तथा (ख). उत्तरोत्तर पंचवर्षीय योजनाओं में अनसूचित आदिम जातियों के कल्याण की सभी योजनाओं का अभिकल्पना अनसूचित आदिम जातियों के आर्थिक तथा सामाजिक स्तर को ऊंचा उठा कर शेष आबादी के स्तर तक लाने के लिये किया गया है । समस्त देश के सामाजिक-आर्थिक विकास के लिये योजना के सामान्य क्षेत्र में की गई व्यवस्थाओं की ये योजनायें पूरक हैं ।

(ग) इस समस्या का स्वरूप इस प्रकार का है तथा इसका विस्तार इतना अधिक है कि उन्हें शेष आबादी के बराबर लाने में कुछ समय लगेगा । इस प्रयोजन के लिये कोई समय-सीमा नियत करना सम्भव नहीं है ।

श्री सिद्धेश्वर प्रसाद : मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार का ध्यान इस बात की ओर गया है कि जो पिछली तीन योजनाएं बनीं उनसे उन्हीं वर्गों को अधिक लाभ हुआ जो आगे थे और जो पिछड़े हुए थे उनको उतना लाभ नहीं मिला और आदिवासियों को और भी कम लाभ पहुंचा, तो इस बात को ध्यान में रखते हुए और पिछले अनुभव को ध्यान में रखते हुए क्या सरकार चौथी योजना में इसके लिए कोई विशेष उपाय करने जा रही है ?